इटली के सिएना शहर के बाहर पुरातत्ववेत्ता वर्ष 2019 से प्राचीन थर्मल बाथ्स (गर्म पानी के कुण्डों) की खुदाई कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में, कुछ समय से मिट्टी और पानी में से झांकते हुए छोटे -छोटे अज्ञात अवशेष दिखाई देने लगेः एक हाथ, एक कोहनी एक चमचमाता सिक्का आदि। इसके बाद से शोधकर्ता यहां से 24 कांस्य मूर्तियां निकाल चुके हैं। बहुत अच्छी तरह से संरक्षित ये मूर्तियां 2300 साल पुरानी हैं। इसके अलावा हजारों सिक्के व अन्य कलाकृतियां भी मिली हैं। यह खोज सिएना के एक छोटे से पहाड़ी कस्बे, सैन कैशानो डी बानी में हुई हैं। सिएना प्रांत थर्मल बाथ्स के लिए जाना जाता है। इतिहासकार जैकोपो टावोली ने बताया कि, "रोमन और एट्रस्कन काल की मूर्तियों का यह सबसे बड़ा जखीरा है। पहली बार इटली में इतना बड़ा भंडार मिला है और यह इटली की और समूचे मैडिटरेनिअन की अब तक की सबसे बड़ी व महत्वपूर्ण खोज है।" ये मूर्तियां दूसरी सदी ईसा पूर्व से पहली सदी इस्वी के बीच की हैं। टस्कन इतिहास में यह भारी उथल -पुथल का समय था। एट्रस्कन की जगह रोमन शासन का प्रादुर्भाव हो रहा था। कई शहरों में भयंकर युद्ध हुए, यह कस्बा भी उनमें से एक था। रोमन्स जीत गए तो उन्होंने एट्रस्कन संस्कृति को प्रभाव शून्य करने के लिए उनकी कलाकृतियों आदि को नष्ट करना या जमीन में गाड़ना शुरु कर दिया। खुदाई में मिली मूर्तियों में हेजीया, अपोलो व अन्य यूनानी रोमन देवताओं की मूर्तियां हैं। इनमें कुछ पर लैटिन व एट्रस्कन भाषा में अभिलेख लिखे हैं। टाबोली ने कहा कि, यह खोज इतिहास को पुनः परिभाषित करती है, क्योंकि, यहां एट्रस्कन और रोमन्स एक साथ पूजा करते थे। टाबोली को लगता है कि, इन मूर्तियों को किसी रस्म के लिए गर्म पानी में डुबोया गया होगा। शोधकर्ता यह नहीं जानते कि ऐसा क्यों किया गया, पर उनका कहना है कि गर्म पानी में डुबोने से ही ये सुरक्षित रही हैं। एक अन्य पुरातत्ववेत्ता, युनिवर्सिटी ऑफ सिएना की चिआरा फर्मो ने बताया कि, एक अलंकृत मूर्ति भी मिली है। यह महिला की मूर्ति है जिसने गले में हार व कानों में झुमके पहने हुए हैं। इससे पता लगता है कि, उस समय महिलाएं कैसी दिखती थीं और उनकी वेशभूषा क्या थी। इस क्षेत्र के थर्मल बाथ्स पांचवी सदी इस्वी तक प्रयुक्त होते थे पर उसके बाद नए ईसाई कानून के तहत सार्वजनिक स्नानागार प्रतिबंधित कर दिए गए।

मुख्यमंत्री कुर्सी बचाने में तो माहिर हैं लेकिन किसी का जीवन बचाने में उनकी कोई रूचि और प्रतिबद्धता नहीं-पूनिया

राजसमंद के देवगढ़ में एक पुजारी दंपती को जिंदा जलाने की घटना पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने यह तीखी टिप्पणी की

जयपुर, 21 नवम्बर (का.सं.)। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने आज मीडिया से बातचीत में प्रदेश की गहलोत सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, राजसमंद के देवगढ़ के हीरा गांव में पुजारी दंपती को जिंदा जलाया जाना प्रदेश में यह पहली घटना नहीं है, और सीधे-सीधे यह राजस्थान के इकबाल से जुड़ी घटना है, जो अपराध की घटनाएं यहां हुई हैं। उसमें पुजारी को जलाने की एक और घटना जुड़ गई।

पुजारी को जिंदा जलाया जाना एक बार फिर कांग्रेस सरकार के सामने सवाल खड़ा कर गया। राजस्थान में कोई भी ना सड़क पर सुरक्षित है, ना घर में, ना मंदिर में, ना अस्पताल में और ना स्कूल में। राजस्थान की असुरक्षा यहां तक पहुंच गई कि देवी-देवताओं को पूजने वाले पुजारी को इस क्रूर तरीके से जिंदा जला दिया जाता है।

यह सीधे-सीधे राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री पर सवाल खड़े करता है, जो इस समय भारत जोड़ने की बात करते हैं पर अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए सारी बातों को ताक पर रख देते हैं, यह उसी का नतीजा है। कानून व्यवस्था पिछले 4 सालों में जिस प्रकार ध्वस्त हो रही है। उसकी परिणति इस वीभत्स रूप में हो रही है।

■ डॉ. पूनिया ने आगे कहा, "राजसमंद के देवगढ़ की घटना ने एक बार फिर उद्वेलित कर दिया। राजस्थान में माफिया और बदमाशों का आतंक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राजनीतिक संरक्षण में साफ तौर पर दिखता है कि, ऐसी घटनाओं से वह आंख मूंदकर बैठे हैं।

उन्होंने कहा, कांग्रेस शासन में अपराध की घटनाएं चरम पर हैं, जहां या तो पुजारी को जिंदा जलने के लिए विवश होना पड़ता है, जैसे महंत विजय दास की घटना हुई, और जयपुर के मुरलीपुरा में जो घटना हुई, राजसमंद के देवगढ़ की इस घटना ने एक बार फिर से सभी उद्वेलित कर दिया है कि किस तरीके से राजस्थान में माफिया और बदमाशों का आतंक है, यह सब अशोक गहलोत के राजनीतिक संरक्षण में हो रहा है। साफ तौर पर दिखता है कि वे ऐसी घटनाओं से आंख मूंदकर बैठे हैं

राज्य सरकार की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के प्रति कोई प्रतिबद्धता दिखती नहीं है, अब ऐसा लगता है कि राजस्थान अपराधियों के हाथों में है, यहां सरकार का ना कोई इकबाल है, ना कोई शासन है, ऐसे में समाज में उद्वेलन स्वाभाविक है प्रदेश में दिन दहाड़े डकैती, हत्याएं होती हैं, लूटपाट की घटनाएं होती हैं, 7 हत्याएं प्रतिदिन के आंकड़े में एक और हत्याकांड जुड़ गया। मुख्यमंत्री कुर्सी बचाने में तो माहिर हैं लेकिन किसी व्यक्ति का जीवन बचाने में उनकी कोई रुचि और प्रतिबद्धता नहीं है।

उत्तर भारत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

समाप्त होने के बाद, ए.आई.सी.सी. का अधिवेशन बुलाया जाये, जिससे कि नई कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव हो सके। उन्होंने प्रत्येक राज्य तथा पार्टी के विभिन्न विभागों एवं अग्रिम संगठनों के काम-काज की विस्तृत रिपोर्ट माँगी हैं। उन्होंने राज्य कांग्रेस कमेटियों प्रत्येक गतिविधियों के दैनिक दस्तावेजीकरण के भी आदेश दिये हैं। खड़गे मई में की उदयपुर घोषणा के ब्लूप्रिन्ट के आधार पर पार्टी का कायाकल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मस्तिष्क में तीन प्रमुख बिन्दु हैं-संगठन, प्रचार-प्रसार एवं संवाद तथा संसाधन। वे चुनाव प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण के लिये आधा दर्जन नये विभाग स्थापित करने की योजना पर काम कर रहे हैं। उनकी योजना एक पब्लिक इनसाइट डिपार्टमेंट स्थापित करने की भी है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पूरे संगठन में 50 प्रतिशत पदाधिकारियों की उम्र 50 वर्ष से कम हो।

'मेरा फोकस...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इसके साथ ही, अजय माकन का मुद्दा भी अभी अनिर्णीत है। उनका इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं हुआ है। लेकिन मूल एवं विवादित प्रश्न यह है कि इस निर्णय में कितना विलम्ब और होगा क्योंकि यात्रा तो राजस्थान पहुँचने को ही है।

राजस्थान के प्रभारी महासचिव से ऐसी आपेक्षा है कि वे राजस्थान में राहुल गांधी को एक नई जीवन्तता देने में मुख्य भूमिका निभायेंगे लेकिन चूँकि माकन प्रभारी महासचिव के काम-काम को अंजाम नहीं दे रहे हैं, इसलिये पार्टी को इस बारे में स्पष्ट विचार बनाना चाहिये। कुल मिलाकर, विलम्ब से शीघ्रता भली।

रेप व हत्या के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तीन दोषियों की रिहाई को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे। इन तीनों अपराधियों को फाँसी की सजा दी गई थी। सक्सेना ने इस केस के लिये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को वकील के रूप में लिये जाने का भी अनुमोदन कर दिया है।

सम्बन्धित अधिकारी ने कहा, "सर्वोच्च न्यायालय के तीन आरोपियों की रिहाई के निर्णय के खिलाफ, सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करने की स्वीकृति उप राज्यपाल ने दे दी है।"

इन तीनों आरोपियों को 9 फरवरी, 2012 को दिल्ली के द्वारका क्षेत्र के छावला स्थान पर 19 वर्षीय युवती के वीभत्स गैंगरेप तथा हत्या के अपराध के लिये ट्रायल कोर्ट ने फाँसी की सजा का फैसला दिया था तथा दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसे यथावत रखा था।

उन्होंने इस सजा के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी तथा सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 7 नवम्बर के फैसले में ट्रायल कोर्ट तथा उच्च न्यायालय के आदेशों की रद्द कर दिया था।

भाजपा सांसद आर. के. पटेल समेत 19 को सजा

चित्रकूट, 22 नवंबर। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिले की एक अदालत ने 13 साल पुराने एक मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद आर. के. पटेल समेत 16 लोगों को एक साल की तथा तीन को एक महीने की सजा सुनायी है। इसके अलावा एक अभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सरकार के कार्यकाल में समाजवादी पार्टी (सपा) कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव और ट्रेन रोकने के मामले में 20 लोगों पर दोष सिद्ध करते हुए बांदा चित्रकूट के सांसद आर. के. पटेल और दस्यु सम्राट ददुआ के बेटे, पूर्व विधायक वीरसिंह समेत 16 लोगों को एक-एक वर्ष की सजा सुनाई। बीस में से एक अभियुक्त, राज बहादुर यादव की मौत हो चुकी है, जबकि महेंद्र गुलाटी, गुलाब और राजेंद्र शुक्ला को एक-एक माह की सजा सुनाई गई है।

■ चित्रकूट जिला अदालत ने बांदा चित्रकूट के सांसद आर. के. पटेल और दस्यु सम्राट ददुआ के बेटे, पूर्व विधायक वीरसिंह समेत 16 लोगों को एक-एक वर्ष की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के वकील ने बताया कि, सन् 2009 में 16 सितम्बर को सपाइयों ने बसपा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था। पुलिस ने 20 लोगों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। इनमें से एक आरोपी, पूर्व सपा जिलाध्यक्ष की मौत हो चुकी है। मौजूदा भाजपा सांसद आर. के. पटेल और मौजूदा भाजपा नगर पालिका चेयरमैन नरेंद्र गुप्ता समेत छह आरोपी पूर्व में समाजवादी पार्टी (सपा) में थे।

क्या राहुल के गुजरात अभियान का भारी असर होगा कांग्रेस की संभावनाओं पर?

राहुल भारत जोड़ो यात्रा को बीच में छोड़कर गुजरात गए, चुनाव प्रचार के लिए, जबकि हिमाचल में उन्होंने कदम भी नहीं रखा

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 नवम्बर। गत 7 सितम्बर से शुरु की गई भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण से पूर्व सूरत और राजकोट में एक-एक रैली को संबोधित किया।

राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रचार से दूर रहे किन्तु सौराष्ट्र में पार्टी के गढ़ से अधिकतम लाभ उठाने को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री के गृह राज्य में चुनाव प्रचार करने का निर्णय लिया। उनके दौरे से दक्षिण गुजरात में भी पार्टी की संभावनाएं मजबूत होने की उम्मीद है। गांधी ने वर्ष 2017 के गुजरात विधानसभा चुनावों में जोर-शोर से प्रचार किया था। तब कांग्रेस ने उम्मीद से अधिक प्रदर्शन कर विधानसभा की कुल 182 सीटों में से 77 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा द्वारा जीती गईं सीटों की संख्या पिछले दो दशकों में पहली बार तिहाई के आंकड़े से कम रही थी और वह 99 सीटें ही जीत सकी थी।

■ कहा जा रहा है कि, उनकी सभाओं से सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात में पार्टी की संभावनाएं और बेहतर होंगी। यह आदिवासी बैल्ट है, जिसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है।

■ वर्ष 2017 में भी राहुल ने गुजरात में भारी चुनाव प्रचार किया था और 182 सदस्यों वाली विधानसभा में 77 सीटें जीती थीं और हालांकि, भाजपा को बहुमत मिला था पर पार्टी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी।

हार्दिक पटेल सहित युवा नेताओं के पार्टी से बाहर जाने और अरविन्द केजरीवाल की आप के गुजरात के चुनाव में उतरने से कांग्रेस को इस वर्ष के चुनाव में सत्ता के मजबूत दावेदार के रूप में नहीं देखा जा रहा, लेकिन पर्यवेक्षक कहते हैं कि राहुल गांधी की अंतिम क्षणों में की गई बातचीत लोगों के दिमाग पर वोट डालने से पूर्व गहरा प्रभाव डाल सकती है।

सौराष्ट्र पारम्परिक रूप से कांग्रेस का गढ़ रहा है। वर्ष 2012 से यहां की 48 सीटों में से कांग्रेस ने 28 सीटें जीतीं थी। भाजपा मात्र 19 ही जीत सकी थी। दक्षिण गुजरात की 35 सीटों में से 2017 में कांग्रेस 10 और भाजपा ने 25 सीटें जीती थी। कांग्रेस नेताओं के अनुसार, राहुल गांधी की रैली इन दोनों क्षेत्रों को प्रभावित करेगी। डांग और वल्साड़ जैसे क्षेत्रों में आदिवासी आबादी भारी मात्रा में है और कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार आदिवासियों की उपेक्षा कर रही है। समझा जाता है कि रैली में राहुल आदिवासियों के उत्थान के लिए कांग्रेस की योजनाएं घोषित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व अन्य स्टार प्रचारक भी गुजरात जा रहे है और मध्य प्रदेश से 23 नवम्बर को गांधी यात्रा से पुनः जुड़ेंगे।

गुजरात में दूसरे चरण का मतदान 5 दिसम्बर को होगा और गुजरात व हिमाचल के लिए वोटों की गिनती 8 दिसम्बर को होगी।

'80 लाख ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन्होंने कहा कि स्टिंग ऑपरेशन में पता चला है कि 110 सीटों के लिए पैसा लिया गया है। बिंदु श्रीराम जिन्होंने यह स्टिंग ऑपरेशन किया है पूर्व में कांग्रेस में थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने केजरीवाल की इस सलाह पर अमल किया सभी लोग भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करें। और इसलिए जब उससे टिकट के एवज में इतनी भारी राशि मांगी गई तो उसने स्टिंग ऑपरेशन किया।

वीडियों में रोहिणी विधानसभा सीट पर आप के समन्वयक पुनीत गोयल को भी दिखाया गया जो किसी आर.आर. पठानिया के करीबी है और मंत्री गोपाल राय के. एन.जी ओ. "देश की बात के प्रभारी है। तीसरा व्यक्ति था दिनेश श्रॉफ, जो आप सांसद सुशील गुप्ता और विधानसभा स्पीकर राम निवास का करीबी है। चौथा व्यक्ति खुद पठानिया है जो आप की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य है तथा दिल्ली राज्य की एस.सी.एसटी. इकाई के प्रभारी भी है।

वीडियों में बिंदु को पुनीत गोयल, श्रॉफ और पठानिया से बात करते दिखाया गया है।

रूस अब "एनर्जी टैररिज़्म"...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रूस एनर्जी की सभी सप्लायी चेन्स तबाह करने की कोशिश में है। इसमें विशेष रूप से ऊर्जा उत्पादन के थर्मल पावर प्लांट्स, ऊर्जा वितरण प्रणालियों और पावर लाइन्स हैं।

यूक्रेन सरकार तबाह हुए इस एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर की जितना जल्दी हो सके उतना रिपेयर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन देश के निवासी और व्यापारिक संस्थान गैस से चलने वाले जनरेटरों और जलाने के काम आने वाली लकड़ियों के लिए हाय-तौबा कर रहे हैं।

गैर लाभकारी युद्ध सहायता संस्थान, संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी सहयोगी देशों ने यूक्रेन को भेजे जाने वाले शिपमैन्ट्स में सर्दियों के कपड़े, मोटे कम्बल और गर्मी देने वाले उपकरणों को शामिल करना शुरू कर दिया है।

इन्टरनैशनल रेस्क्यू कमेटी की यूक्रेन की निदेशक मीरिसिक्षा ज़ैपास्निक कहती हैं कि "यदि दीर्घ अवधि के लिए बिजली कटौती हो जाए तो हमारे पास ऐसे साधन नहीं है जो हम जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध करा सकें। मानवीय स्थिति वर्तमान की तुलना में भी और भयावह हो जाएगी।"

यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि रूस के हमलों से अक्टूबर माह के अंत तक देश का करीब 40 प्रतिशत थर्मल उत्पादन नष्ट हो चुका है और 90 प्रतिशत पवन ऊर्जा तथा 40 प्रतिशत से अधिक सौर ऊर्जा स्त्रोतों पर या तो कब्जे कर लिए गए है अथवा उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया गया है।

यूक्रेन के सबसे बड़े निजी ऊर्जा उत्पादक डी.टी.ई. के का कहना है कि रूस के हाल ही हुए हमलों में ऊर्जा की वितरण प्रणालियों को निशाना बनाया गया।

डी.टी.ई. के एक बयान में कहता है कि "इन कार्रवाईयों को ऊर्जा आंतकवाद और यूरोप के बिलकुल मध्य में एक मानवीय त्रासदी उत्पन्न करने के नृशंस प्रयास के अलावा कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

कीव स्थित एनर्जी रिसर्च सैन्टर के निदेशक ऑलैक्ज़ैडंर खारचेंकों कहते हैं कि ऊर्जा सब स्टेशन्स और ट्रांसफॉर्मर्स पर हो रहे हमले ऊर्जा को स्थानांतरित करने और यूरोप से ऊर्जा आयात करने की यूक्रेन की क्षमता को सीमित करते हैं। अब भी कई ऐसे महत्वपूर्ण ठिकाने हैं जिन्हें लम्बी दूरी के हमलों से बचाने की आवश्यकता है।

खारचेंकों कहते हैं कि "मेरा मानना है कि यूक्रेन के पास बिजली उत्पादन की पर्याप्त क्षमता है, युद्ध की शुरूआत से ही उत्पादन सुविधाओ को ढंग से सुरक्षित रखा गया है, लेकिन सबस्टेशन्स की संख्या काफी है। स्पेशल एयर डिफैंस सिस्टम के जरिए इन सभी को कवर करना संभव नहीं है।

इस भयावह स्थिति में उम्मीद है कि यूक्रेन के लाखों लोग अपने घरों को गर्म रखने के लिए जलाने की लकड़ियों का उपयोग करेंगे। यूक्रेन में लकड़ी जलाने वाले स्टोब्ज और बॉयलर्स की भारी मांग रहती आयी है।

अब इन्हें खरीदना इतना भारी पड़ रहा है कि टैरिटोरियल डिफैंस यूनिट्स ने सैनिकों के लिए मेंटल की शीट्स को वैल्ड करके स्टोव बनाने शुरू कर दिए हैं क्योंकि इन सैनिकों को ही युद्ध के अग्रिम मोर्चे पर सर्दियां बितानी हैं।

कुछ आधारभूत मुद्दों पर भी पार पानी है। नागरिकों को लकड़ियां खरीदने के लिए समर्थ बनाने की भी जरूरत है क्योंकि खाद्य पदार्थो और दवाईयों जैसी दैनिक वस्तुओं की कीमत बढ़ने के साथ ही लकड़ियों के भी भाव बढ़ गए हैं। जलाने वाली लकड़ियों को डिलीवर करना भी चिन्ता पैदा कर रहा है क्योंकि युद्ध से त्रस्त दूरस्थ स्थानों में इन्हें कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा।

क्या तमिल "कल्चर" चाबी है भाजपा का दक्षिण ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कि वह तमिल भाषा संस्कृति एवं विरासत को महत्व दे रही है तो क्षेत्रीय दलों के लिये भाजपा को रोक पाना बहुत मुश्किल हो जायेगा। दरअसल द्रविड पार्टियाँ अब तक यह दावा करती आ रही थीं कि वे तमिल भाषा, संस्कृति एवं विरासत को बाहरी प्रभावों से बचाये हुये हैं।

आई.आई.टी. मद्रास तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस समारोह में तमिलनाडु के विभिन्न स्थानों के 2500 स्कूल-कॉलेजों के विद्यार्थियों को लाने की व्यवस्था की जा रही है। उद्घाटन समारोह में विख्यात संगीतकार इल्लैराजा ने रुद्रम के श्लोकों से शिव-वन्दना प्रस्तुत की, जिसे तमिल समाचार चैनलों पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाषण के साथ, लाइव टेलीकास्ट किया गया। राजनैतिक विश्लेषक एस. राजागोपालन, जिन्हें दक्षिण भारत की गहरी समझ है, का कहना है, "मूल बात यह है कि "काशी-तमिल संगमम" भाजपा की "लुक साउथ" नीति का शुभारम्भ है।" उन्होंने कहा कि सच बात यह है कि अलग-अलग राज्य के लिये भाजपा की अलग-अलग रणनीति रहती है। उत्तर प्रदेश के लिये बुलडोज़र की राजनीति, महाराष्ट्र, दिल्ली तथा पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय का उपयोग। उन्होंने आगे कहा कि "झारखंड तथा तेलंगाना में, भाजपा के. चन्द्रशेखर राव पर हमले शुरु कर दिये हैं।"

राजागोपालन ने कहा कि तमिलनाडु जो भाजपा के "साउथ प्लान" का सबसे प्रमुख राज्य है, में अपनी पैठ बनाने के लिये वह तमिल संस्कृति पर भरोसा कर रही है तथा इस राज्य ने भाजपा को फायदा पहुँचाना शुरु कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं, इस साल मई से लेकर अब तक, तमिलनाडु के चार दौरे कर चुके हैं तथा अधिकांश केन्द्रीय मंत्री समय-समय पर तमिलनाडु के दौरे पर जाते रहेंगे। तमिलनाडु ही क्या, पूरे दक्षिण भारत में, भाजपा ने बड़े नेताओं के दौरों की झड़ी लगा दी है तथा लगाती रहेगी तथा उसका एकमात्र उद्देश्य है- छः दक्षिण भारतीय राज्यों की 130 लोकसभा सीटों में से अधिकतम सीटें जीतना।

तमिलनाडु में विपक्ष कमजोर है, इसलिये भाजपा को इस राज्य पर कब्जा जमाने का अवसर मिल गया है क्योंकि विपक्षी पार्टी ए.आई.ए.डी.एम. के अपने ही आंतरिक मसलों में उलझी हुई है। इसलिये भाजपा के प्रसार से ही डी.एम.के. भी चिन्तित होने लगी है। ये सब कारण मिलकर राज्य की "रिवॉल्विंग डोर पॉलिटिक्स", जिसमें डी.एम.के. तथा ए.आई.ए.डी.एम.के. बारी-बारी से सत्ता में आया करती थी, में अब अनिश्चितता की स्थिति पैदा कर रहे हैं।

'महिला सम्मन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कानून एवं गृह मामलों के मंत्रालयों को नोटिस जारी कर इस पर जवाब मांगा।

सैक्शन 64 कहता है कि अगर किसी कारणवश संबंधित व्यक्ति सम्मन ना ले सके तो सम्मन की प्रति उस व्यक्ति के परिवार के साथ रह रहे किसी पुरुष सदस्य को दी जाए और आवश्यक समझे तो सम्मन देने वाला अधिकारी सम्मन की एक अन्य प्रति पर उक्त व्यक्ति के हस्ताक्षर भी करवा सकता है।

याचिका कहती है कि जिस व्यक्ति को सम्मन दिया गया है अगर उसके परिवार में सिर्फ महिला ही है, या सम्मन दिए जाने के समय सिर्फ महिला घर पर हो तो क्या किया जाए यह बात उक्त नियम में स्पष्ट नहीं है।

याचिका कहती है कि, 78 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं घर पर रहती है। ऐसे में सम्मन दिए जाते वक्त घर पर महिला सदस्य के होने की संभावना ज्यादा होती है यह याचिका वकीला कुश कालरा ने दायर की है।

याचिका में भाग 64 को रद्द करने के लिए आदेश देने की मांग की गई है।

आय के साधनों के खिलाफ आत्मघाती नीति क्यों अपना रही है रोडवेज?

टैन्डर को पूरा नहीं कर सकने वाली कम्पनी की नियम अनुसार "बैंक गारंटी" जब्त करने के लिए भी तर्क नहीं प्रस्तुत कर पाई रोडवेज

जयपुर, 21 नवम्बर (का.सं.)। राजस्थान रोडवेज द्वारा 48 ए.सी. इलेक्ट्रिक बसों का टेंडर निरस्त किये जाने के बावजूद राजस्थान रोडवेज ने इस कंपनी ग्रीन सेल मोबेलिटी प्राईवेट लिमिटेड द्वारा टेंडर में भाग लेने के लिये जमा की गई बैंक गारंटी, जो 2.82 करोड़ है, को जब्त नहीं कर पाई। गौरतलब है कि कम्पनी टेंडर का कार्य पूरा नहीं कर पाई थी। इसलिए उसका टेंडर निरस्त किया गया था।

इस प्रकरण में ऐसा प्रतीत होता है कि रोडवेज के अधिकारियों की ढिलाई और मिली भगत ही रोडवेज के लिये भारी पड़ी और रोडवेज की हक की राशि उसको नहीं मिल पाई।

उल्लेखनीय है कि इस मामले में रोडवेज के साथ अनुबंधन के अनुसार इस टेंडर को निरस्त करने के बाद रोडवेज 31 दिसम्बर 2022 तक कभी भी ग्रीन सेल मोबेलिटी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से दी गई बैंक गारंटी को जब्त कर सकती है।

परंतु जैसे ही रोडवेज के अधिकारियों ने अक्टूबर, 2022 में इस बैंक गारंटी को जब्त करने के लिये संबंधित बैंक को पत्र लिखा, तब कई कारणोंवश बैंक तुरंत इस बैंक गारंटी की राशि को रोडवेज के पक्ष में जारी नही कर सका। यहां चौंकाने वाली बात यह है कि जैसे ही रोडवेज ने बैंक को 2.82 करोड़ रुपये की राशि जारी करने के लिये पत्र लिखा, वैसे ही ग्रीन सेल मोबेलिटी ने जयपुर के कॉमर्शियल कोर्ट में आवेदन दायर किया और 1 नवम्बर 2022 को ही अदालती आदेशों की मदद से बैंक गारंटी जब्त करने पर रोक लगवा दी।

■ नियमों तथा अनुबंधनों की शर्तों के अनुसार रोडवेज टेन्डर में भाग लेने के लिए दी गई "बैंक गारंटी" टेन्डर का कार्य पूरा नहीं किये जाने की स्थिति में 31 दिसम्बर 2022 तक जब्त कर सकती है।

इस मामले में ग्रीन सेल की ओर से जहां वरिष्ठ और जाने-माने अधिवक्ताओं को पैरवी के लिये नियुक्त किया गया था, वहीं रोडवेज की ओर से पेश हुए अफसर बैंक गारंटी भुनाने के पक्ष में कोई तर्क प्रस्तुत नहीं कर पाये जबकि दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि रोडवेज ही इस बैंक गारंटी राशि की असली हकदार है।

जैसा कि विदित है कि रोडवेज ने 48 ए.सी. इलेक्ट्रिक बसों का टेंडर जारी करने के बाद ग्रीन सेल मोबेलिटी से दिसम्बर 2019 में अनुबंधन किया था। परंतु कंपनी द्वारा इस अनुबंधन की शर्तों को पूरा नहीं कर पाने की वजह से रोडवेज ने इस टेंडर को निरस्त कर दिया था।

प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार ग्रीनसेल इस प्रोजेक्ट के संबंध में अन्य पार्टियों के साथ आधारभूत ढ़ाचा बनाने के लिये किये गये अनुबंधन की कॉपी नहीं प्रदान कर पाई और साथ ही एस्क्रो बैंक अकाउंट भी नहीं बना पाई।

इस मामले को जानने वाले सूत्रों ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी बसों को चलाने के लिये दिल्ली-जयपुर हाइवे पर कई अलग-अगल जगह बसों को चार्ज करने के लिये फैसिलिटी (सुविधा) का निर्माण पूरा नहीं किया गया था। जिस वजह से यह बसें कभी भी काम नहीं कर पातीं।

अब इस मामले में कॉमर्शियल कोर्ट के समक्ष 22 नवम्बर को अगली बहस होगी।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908